



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 213]
No. 213]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 13, 2008/ज्येष्ठ 23, 1930
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 13, 2008/JYAISTHA 23, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2008

विषय : चीन जनगण, के मूल के अर्थात् वहां से निर्यातित पावर स्टियरिंग गियर सिस्टम के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की शुरुआत ।

सं. 14/13/2007-डीजीएडी.—मै. राजे टी. आर. डब्ल्यू. स्टियरिंग सिस्टम लि., चेन्नई तथा मै. जेड एफ गियर (इंडिया) लि., पुणे ने 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिन्हें एतदपरचात् नियम कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपरचात् प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन. गण. (जिसे एतदपरचात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अर्थात् वहां से निर्यातित पावर स्टियरिंग गियर सिस्टम (जिसे एतदपरचात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के कथित पाटन के बारे में पाटनरोधी जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया है ।

और, जबकि, प्राधिकारी ने पाया है कि संबद्ध देशों द्वारा संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं इसलिए प्राधिकारी ऐसे किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए तथा पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश करने के लिए, जिसे यदि लगाया जाता है तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, उक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच के लिए एतद्वारा इस जांच की शुरुआत करते हैं ।

घरेलू उद्योग

2. यह आवेदन मै. राजे टी. आर. डब्ल्यू. स्टियरिंग सिस्टम लि., चेन्नई तथा मै. जेड एफ स्टियरिंग गियर (इंडिया) लि., पुणे द्वारा टी पी एम कन्सल्टेंट्स, नई दिल्ली के माध्यम से, घरेलू उद्योग की ओर से दायर किया गया है । उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार, आवेदक घरेलू उद्योग की ओर से पाटनरोधी शुल्क जांच हेतु मामला दायर करने के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3)(क) के अनुसार पात्रता रखते हैं ।

विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद मध्यम एवं भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए पावर स्टियरिंग गियर सिस्टम है जो संयोजित अथवा नहीं, पूर्ण अथवा अपूर्ण तथा उसके कुछ संघटक अर्थात् पावर स्टियरिंग गियर, पावर स्टियरिंग पम्प तथा उन दोनों का संयोजन है। मध्यम वाणिज्यिक वाहन वह होता है जिसकी भार वहन क्षमता 12 से 16 टन की रेंज में होती है तथा भारी वाणिज्यिक वाहन वह होता है जिसकी भार वहन क्षमता 16 से 40 टन की रेंज में होती है।

4. विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अध्याय 87 (गियर) के उपशीर्ष 87089400 तथा अध्याय 84 (पम्प) के उपशीर्ष सं० 84138190 के तहत वर्गीकृत है। यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

समान उत्पाद

5. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित पावर स्टियरिंग गियर सिस्टम तथा चीन से निर्यातित पावर स्टियरिंग गियर सिस्टम के बीच कोई विशेष अंतर नहीं है। याचिकाकर्ता के अनुसार भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित तथा चीन से आयातित पावर स्टियरिंग गियर सिस्टम भौतिक एवं रासायनिक/यांत्रिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी कार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय है। दोनों उत्पाद तकनीकी एवं वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापनीय हैं तथा उपयोक्ताओं ने इन दोनों उत्पादों को एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग किया है। अतः जांच के प्रयोजनार्थ पाटनरोधी नियम के अर्थ के भीतर आवेदक द्वारा उत्पादित पावर स्टियरिंग गियर सिस्टम को संबद्ध देश से आयातित पावर स्टियरिंग गियर सिस्टम के समान वस्तु माना जा रहा है।

शामिल देश

6. वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जन गण है।

सामान्य मूल्य

7. याचिकाकर्ता ने प्रस्ताव किया है कि चूंकि चीन एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था है अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध - 1 के पैरा 7 के संदर्भ में किया जाए। आवेदकों ने कहा है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था में कीमतें, अर्थात् तीसरे देश से अन्य देशों को प्रस्तावित तीसरे देश की कीमत प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। तदनुसार आवेदकों ने प्रस्ताव किया है कि चीन के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण जांच अवधि हेतु लागू सीमाशुल्क को घटाने के बाद अलग करके भारत में कीमतों के आधार पर किया जाए।

निर्यात कीमत

8. आवेदकों ने आई बी आई एस द्वारा संकलित आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। आवेदकों ने निवल निर्यात कीमत का अनुमान सी आई एफ कीमत के आधार पर किया तथा कारखाना द्वार पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए समुद्री भाड़े, कमीशन इत्यादि पर समायोजन की विभिन्न पद्धतियों को अपनाया है।

पाटन मार्जिन

9. इस बात के पर्याप्त साक्ष्य है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य उनकी निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्ट्या यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

10. आवेदकों ने कथित पाटन के परिणामस्वरूप पाटित आयातों की बढ़ती मात्रा, कीमत कटौती, गंवाई गई बिक्री तथा घरेलू उद्योगों द्वारा लगाई गई पूंजी पर आय में गिरावट के रूप में हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। संबद्ध देश से पाटित आयातों द्वारा याचिकाकर्ताओं को हुई वास्तविक क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य मौजूद है।

जांच की अवधि

11. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 जनवरी, 2007 से 31 दिसम्बर, 2007 तक की है। तथापि क्षति जांच अवधि में अप्रैल 2004 - मार्च 2005, अप्रैल 2005 - मार्च 2006, अप्रैल 2006 - मार्च 2007 तथा जांच अवधि शामिल होगी।

सूचना प्रस्तुत करना

12. संबद्ध देश के निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में और तंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से लिखा जा रहा है। वर्तमान जांच में भाग लेने का इच्छुक कोई अन्य पक्षकार निम्नलिखित पते पर अपने अनुरोध भेज सकता है।

**निर्दिष्ट प्राधिकारी,
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
वाणिज्य विभाग,
कमरा सं० 240, उद्योग भवन,
नई दिल्ली-110007**

समय सीमा

13. इस जांच से संबंधित कोई सूचना लिखित में भेजी जाए जो प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिन) से पूर्व पहुँच जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त हुई सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी उपरोक्त नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

14. नियम 7 के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई किसी भी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करना होगा और यदि ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार की राय में ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा तो उसके कारण का विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

15. नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश रखे हुए हैं।

16. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th June, 2008

Subject : Initiation of Anti-Dumping investigations concerning imports of Power Steering Gear System originating in or exported from China PR.

No. 14/13/2007-DGAD.—M/s. Rane TRW Steering System Ltd., Chennai and M/s. ZF Steering Gear (India) Ltd., Pune have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on dumped articles and for determination of injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as Rules) for initiation of anti-dumping investigation concerning alleged dumping of Power Steering Gear System (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as subject country).

AND WHEREAS, the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of subject goods by the subject country, injury to the domestic industry and causal links between the dumping and injury exist, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the said Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Domestic Industry

2. Application has been filed by M/s Rane TRW Steering System Ltd., Chennai and M/s ZF Steering Gear(India) Ltd., Pune through TPM Consultants, New Delhi on behalf of the domestic industry. As per the evidence available applicants have the standing to file the case for anti dumping investigation on behalf of domestic industry as per Rule 2(b) and Rule 5(3)(a) of Anti Dumping Rules.

Product under consideration

3. The product under consideration is Power Steering Gear System for medium and heavy Commercial vehicles whether or not assembled, complete or incomplete and certain parts thereof, namely, Power Steering Gear, Power Steering Pump and any combination thereof. The medium commercial vehicle is one which is having weight carrying capacity in the range from 12 to 16 ton, while heavy commercial vehicle is one which is having weight carrying capacity in the range from 16 to 40 ton.

4. The product under consideration is classified under Customs Tariff Chapter 87 (Gear) at sub-heading 87089400 and Chapter 84 (Pump) at sub-heading No.84138190. The Custom classification is indicative only and not binding on the scope of investigation.

Like Articles

5. Petitioner has claimed that there is no significant difference in power steering gear system produced by the domestic industry and power steering gear system exported from China. According to the petitioner, power steering gear system produced by the Indian industry and imported from China are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical/mechanical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and consumers have used the two interchangeably. Therefore, for the purpose of investigation the Power Steering Gear System produced by the applicant is being treated as like articles of Power Steering Gear System imported from subject country within the meaning of the Anti Dumping Rules.

Countries involved

6. The country involved in the present investigation is China PR.

Normal value

7. The applicant have proposed that China being a Non Market Economy the normal value is to be determined in terms of Para 7 of Annex-I of Anti Dumping Rules. The applicants have stated that they have not been able to procure the prices in the Market Economy, Third Country price, from such third country to others. Accordingly, the applicants have proposed that Normal Value in respect of China may be determined on the basis of prices in India after deducting the Customs duty applicable for POI.

Export Price

8. The applicants have worked out export price based on the data compiled by IBIS. The net export price has also been estimated by the applicant based on the CIF price and adopting various elements of adjustments towards ocean freight, commission, etc. to arrive at net export price at ex-factory level.

Dumping margin

9. There are sufficient evidences that the normal value of the subject goods in subject country are significantly higher than their net export price prima-facie indicating that the subject goods are being dumped by the exporters from the subject country.

Injury and Causal Link

10. The applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of fall in their market share because of increased volume of dumped imports, price undercutting, lost sales and decline in return on capital employed for the domestic industries. There is sufficient prima-facie evidence of the material injury being suffered by the applicants caused by dumped imports from subject country.

Period of investigation

11. The period of investigation for the purpose of present investigation is 1st January 2007 to 31st December, 2007. The injury investigation period will however cover the periods April 2004–March 2005, April 2005–March 2006, April 2006–March 2007 and the Period of Investigation (POI).

Submission of information

12. The exporters in the subject country and their Government through their Embassy in India, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other party interested to participate in the present investigation may write to:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce
Room No.240, Udyog Bhavan,
New Delhi-110107.

Time limit

13. Any information relating to this investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of publication of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

Submission of Information on Non-Confidential basis

14. In terms of Rule 7, the interested parties are required to submit non-confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summarization, a statement of reason thereof, is required to be provided.

INSPECTION OF PUBLIC FILE

15. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

16. In case where an interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

R. GOPALAN, Designated Authority